प्रेस विज्ञप्ति

एक भारतीय संसदीय सद्भावना शिष्टमंडल ने दोनों देशों के बीच संसदीय संबंधों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने के लिए माननीय संसदीय कार्य तथा कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में 31 मई से 3 जून, 2017 के दौरान नार्वे का दौरा किया।

संसदीय शिष्टमंडल में श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा), बी.जे.डी., डॉ. हीना विजयकुमार गावित, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी, संसद सदस्य (लोक सभा), टी.आर.एस., श्री चंद्रकांत भाऊराव खैरे, संसद सदस्य (लोक सभा), शिव सेना, श्री राम कुमार वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा), बी.जे.पी., श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य (लोक सभा), आई.एन.सी., श्री पलानीवेल कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा), ए.आई.ए.डी.एम.के., श्री चिंतकुंटा मुनैया रमेश, संसद सदस्य (राज्य सभा), टी.डी.पी., श्री मोहम्मद फैजल पादीपुरा, संसद सदस्य (लोक सभा), एन.सी.पी. और श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, संसद सदस्य (लोक सभा), वाई.एस.आर.सी.पी. और सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री राजीव यादव शामिल थे।

1 जून, 2017 को माननीय मंत्री के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल ने सुश्री अन्नीकेन ह्यूटफेल्ट, अध्यक्ष, विदेश नीति और रक्षा संबंधी स्थायी समिति, श्री गुन्नार गुंदेर्सन, उपाध्यक्ष, व्यापार और उद्योग संबंधी स्थायी समिति और सुश्री मारिट बर्जर रॉसलैंड, विदेशी मामलों की राज्य सचिव से मुलाकात की। 2 जून, 2017 को माननीय मंत्री के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल ने सुश्री मोनिका मेलैंड, व्यापार और उद्योग मंत्री से मुलाकात की और नार्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-इकॉनोमी रिसर्च (एन.आई.बी.आई.ओ.), ऐज, नार्वे का दौरा किया।

माननीय मंत्री श्री अहलुवालिया ने, नार्वेजियन संभाषियों के साथ अपनी मुलाकातों में, बताया कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है और मानवाधिकारों के उपभोग में अड़चन डालता है और लोकतांत्रिक समाजों के सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। माननीय मंत्री ने आतंकवाद, जो बड़े लोगों से संबंध रखने वाले, पढ़े-लिखे, वित्त-पोषित, शस्त्रों से लैस और प्रशिक्षित है, का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकजुट होने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत जोरदार ढंग से आतंकवाद की निंदा करता है और कहा कि आतंकवादियों को आश्रय, शस्त्र, प्रशिक्षण या धन प्रदान करने वाले देशों के लिए कोई सहिष्णुता नहीं हो सकती।

माननीय मंत्री श्री अहलुवालिया ने बताया कि भारत और नार्वे दोनों को समुद्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी और जैविक कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि पुन:परिचालन जलकृषि प्रणाली (आर.ए.एस.) शुरू करना भारत के लिए पूरी तरह से नया है जबकि नार्वे की कंपनियों को इस उच्च-प्रौद्योगिकीय उत्पादन तकनीक में दक्षता हासिल है। भारत

पुन:परिचालन जलकृषि प्रणाली (आर.ए.एस.) को विकसित करने के लिए नार्वे से ज्ञान और तकनीकी दक्षता का आदान-प्रदान करने के लिए विशेषज्ञता और सहयोग की आशा करता है।

उन्होंने उल्लेख किया कि दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में कई पहल और अन्य बहुपक्षीय अभियानों में एक दूसरे का समर्थन किया है और उन्होंने इस सहयोग को और सुदृढ़ करने और संयुक्त राष्ट्र में कई मुद्दों पर हमारी बातचीत को और बढ़ाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। **उन्होंने पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के साथ-साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी के लिए नार्वे सरकार के बहुमूल्य समर्थन के लिए हार्दिक प्रशंसा व्यक्त की।**

माननीय मंत्री और शिष्टमंडल ने नार्वे में भारतीय राजदूत श्री देबराज प्रधान द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय और प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।

भारत के इस उच्चस्तरीय संसदीय शिष्टमंडल के दौरे से भारत-नार्वे के संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

...

ओस्लो, 03 जून, 2017